भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1824

उत्तर देने की तारीख-10.03.2025

महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और हाई स्कूलों हेतु सरकारी योजनाएं

†1824. **श्री अब्दुल रशीद शेख**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी और सरकारी डिग्री कॉलेजों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या जम्मू और कश्मीर में निजी कॉलेजों, यदि कोई हो, को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) मार्च, 2023 से विगत दो वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और हाई स्कूलों को प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): एआईएसएचई 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार, देश में निजी और सरकारी डिग्री महाविद्यालयों की राज्यवार कुल संख्या https://www.education.gov.in/parl_ques पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप संस्थाओं की गुणवत्ता को सुधारने हेतु नई संस्थाओं, विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, तथा सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को निधि प्रदान करना है।

सरकार द्वारा शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसए) के रूप में जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निधियां

जारी की जाती है। यूजीसी जम्मू और कश्मीर सहित निजी स्व-वित्तपोषित महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है।

विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान यूजीसी द्वारा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को पीएम-यूएसएचए के अंतर्गत और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विद्यालयों को समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत जारी निधियों का विवरण https://www.education.gov.in/parl_ques पर उपलब्ध है।

***